

मईयां योजना कोई प्रसाद नहीं, उनका हक है

■ हेमंत सरकार ने ग्रामीणों की आर्थिक संपन्नता की परिकल्पना की

■ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रूरल इकॉनमी को मजबूत करने की जरूरत

झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड के अनुभवी नेताओं में से एक हैं। वह झारखंड को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। राधाकृष्ण किशोर छह बार के विधायक हैं। वित्त मंत्री के रूप में झारखंड के विकास मॉडल पर वह बेबाक राय रखते हैं। “आजाद सिपाही”



यह हेमंत सोरन की सरकार ही है जिसने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक संपन्नता की परिकल्पना की है।

सवाल: हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में फिलहाल झारखंड की जो मौजूदा स्थिति है, जो विकास की गति है, आपकी नजर में फिलहाल झारखंड अभी कहाँ स्टैंड करता है ?

जवाब: झारखंड जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अभी उस पर बहुत काम करना बाकी है। वह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन यह हेमंत सोरन की सरकार ही है, जिसने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक संपन्नता की परिकल्पना की है। यह स्टेट रेन शैडो एरिया में पड़ता है, हर एक साल के बाद इस राज्य को सुखाड़ का सामना करना पड़ता है और हमारी जो रूरल इकॉनमी है, वह एग्रीकल्चर पर आश्रित है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, जब यह राज्य और यहां के किसान सुखाड़ का सामना कर रहे होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है, वह अत्यंत ही कमजोर हो जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहला फोकस है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाये और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से मत्स्य पालन, दुध उत्पादन, पशुपालन, तालाब में अगर पानी उपलब्ध कराया जाये तो मछली पालन बहुत ही सुलभता के साथ किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे सकेंगे नौजवानों को और रूरल इकॉनमी को मजबूत भी कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन झारखंड में

से बातचीत से दौरान मईयां सम्मान योजना से लेकर ग्रामीणों के आर्थिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर राज्य के विकास पर



उद्योग की स्थापना हो रही है, या की जा रही है तो फिर उसकी मार्केटिंग अगर दूसरे राज्य में और दूर दराज के राज्य में हो रही है, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह फीजिबल होगा या नहीं होगा। तो मेरे दृष्टिकोण से जो भी हमारे पास माईस मिनरल्स हैं, तो उससे मिलने वाली जो रॉयकटी है, जो पैसा है, वो राज्य सरकार को मिले, तो हम रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं।

सवाल: झारखंड का बजट जो 2024-25 का रहा, एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का, लेकिन अभी झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जैसे मईयां सम्मान योजना है और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन, फ्री बिजली भी है, गैस सिलिंडर भी देना होगा, अबुआ आवास भी देना है, तो जो अमाउंट है वह तो निर्धारित अमाउंट है, योजना में आप देंगे ही, विकास कार्य में पैसा लगाना भी है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ?

जवाब: एक, जो कुछ लोगों के मन में बातें आती हैं, सार्वजनिक रूप से कि मईयां सम्मान योजना को एक प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और वोट की राजनीति के तहत किया जा रहा है, यह गलतफहमी है, मैं इसे दूर करना चाहता हूं। देखिये, आप भी झारखंड से हैं, हम लोग भी झारखंड से हैं। हमने देखा है कि गांव की स्थिति क्या है, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है। जो गांव की महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं,

उनकी क्या स्थिति है। आप चले जाइए किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जितने सारे गांव हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में उनके पास नगद राशि भी नहीं है कि छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए वो दवा खरीद सकें। मईयां सम्मान योजना को अब 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये होने जा रही है, ये पैसा जब उनके हाथ में जायेगा, तो वे अपनी जरूरत की



मईयां सम्मान योजना जो 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये होने जा रही है, ये पैसा जब उनके हाथ में जायेगा, तो वे अपनी जरूरत की चीजों को खुद ले सकेंगी। खरीद सकेंगी।

चीजों को खुद ले सकेंगी। खरीद सकेंगी। **काटते हुए सवाल:** लेकिन सरकार पर इसका अतिरिक्त भार भी तो पड़ेगा ?

जवाब: मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। देखिये वो पैसा जब खर्च होगा, तो वह गांव के बाजार में खर्च होगा, रिमोट एरिया के मार्केट में खर्च होगा। वह पैसा जो वहां खर्च होगा,

अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार मजबूती से झारखंड के विकास मॉडल को विकसित करने में लगी



आप सिर्फ एक गांव को नहीं देखें, आप उन सभी लाभान्वित को देखें तो उनके द्वारा खर्च किया गया पैसा, घूम फिर कर के जीएसटी के माध्यम से और दूसरे टैक्सेस के माध्यम से वापस राज्य सरकार के खजाने में आयेगा। मुफ्त चूल्हा की स्थिति नहीं होगी कि एक बार दे दिया और फिर वह पड़ा का पड़ा रह गया। यह जो हम दे रहे हैं वापस यह पैसा किसी ना किसी रूप से राज्य के खजाने में आयेगा और उसका एक निश्चित भाग हमें प्राप्त होगा। जहां तक आपने अतिरिक्त भार का सवाल किया है तो यह इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं है कि अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। देखिए हर पांचवा वर्ष झारखंड के लिए चुनावी वर्ष होता है। झारखंड राज को दो चुनाव का सामना करना पड़ता है, एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा। तो चार पांच महीने तो आदर्श आचार संहिता में लग जाते हैं, चाहे कर भी सरकार योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाती। तो खर्च की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। हम लोग इस बात का आकलन करेंगे कि कौन ऐसा विभाग है जो चार महीने, छह महीने के बीच में जितना उसको खर्च कर लेना चाहिए था, जो आदर्श आचार संहिता लगने के कारण खर्च नहीं कर पाया, हम उसमें एक निश्चित परसेंटेज में अमाउंट का कटौत करके, मईयां सम्मान योजना को देंगे ताकि वह प्रभावकारी हो सके। ऐसे भी वह पैसा अगर उनके पास रह जाये,

है। कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक स्पष्ट विजन के साथ सभी को टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन ही झारखंड को आगे ले जायेगा। यहां पेश है **आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह** के साथ उनकी बातचीत के प्रमुख अंश।

ओड़िशा, जो उसके मॉडल का अध्ययन करे, ताकि हम उसको अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर सकें।

सवाल: आपको, आपके अनुभव से क्या लगता कि झारखंड में वह एक चीज, एक क्षेत्र, या सेक्टर क्या हो सकता है जहां राज्य सरकार फोकस करे, तो पूरा झारखंड का आर्थिक मॉडल रिवाइव हो सकता है। वो कौन सा फोकस पॉइंट हो सकता है जिससे झारखंड का विकास तेजी से हो सके ?

सिर्फ टैबलेट से आप किसी कुपोषित बच्चे की समस्या का हल नहीं ढूँढ सकते

जवाब: झारखंड में दो-तीन चीजें ऐसी हैं, जिस पर हम फोकस करना चाहेंगे और सरकार का ध्यान भी केन्द्रित करना चाहेंगे। एक तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी। दूसरा यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में एनआरएचएम पांच की रिपोर्ट है कि लगभग 65 से 70 प्रतिशत महिलाएं एनेमिक हैं। खून की कमी से ग्रस्त हैं और जीरो टू पांच वर्ष के जो बच्चे हैं, वे लगभग 45 से 55 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं। तो इसमें एक दो विभागों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिर्फ टैबलेट से आप किसी कुपोषित बच्चे की समस्या का हल नहीं ढूँढ सकते हैं। या बीमारी का इलाज नहीं ढूँढ सकते हैं। उसको प्रॉपर डाइट भी मिलनी चाहिए। वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर फूड एंड सिविल सप्लाय हो, जो हमारी व्यवस्था है, वह इतनी मजबूत हो, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, फिर स्कूल में जो डाइट की आपूर्ति की जाती है उसके माध्यम से, वह सशक्त हो। दूसरी बात यह है कि मेडिकल फैसिलिटी गांव में हो ताकि उनका इलाज सुलभता पूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जाये, ये हमारा फोकस है।



सिर्फ टैबलेट से आप किसी कुपोषित बच्चे की समस्या का हल नहीं ढूँढ सकते हैं। किसी बीमारी का इलाज नहीं ढूँढ सकते हैं। उसको प्रॉपर डाइट भी मिलनी चाहिए।

एग्रीकल्चर, एलाइड एग्रो सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत

तीसरा रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हम दोनों सेक्टर पर काम करना चाहेंगे। हेमंत सरकार काम करना चाहेंगी। एक तो वाटर कंजर्वेशन, जिसमें आपका एग्रीकल्चर ,जो इरिगेशन फैसिलिटी है, वो भी आता है। दूसरा एलाइड एग्रो सेक्टर को मजबूत करने से यह राज्य रूरल एरिया में भी और शहरी एरिया में भी इकॉनमी को मजबूती प्रदान कर सकता है।

झारखंड के बेटे की मलेशिया में गयी जान

परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से शव वापस लाने की लगायी गुहार

आजाद सिपाही संवाददाता

बोकारो। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचटी थाना के करीबुर्द ग्राम निवासी जगदीश महतो की मौत मलेशिया में मंगलवार को टावर से गिरने हो गयी। मौत के बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगायी है।

काम करने गया था मलेशियारू : चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत करीबुर्द निवासी शनिचरा महतो के 22 वर्षीय पुत्र जगदीश महतो मलेशिया में काम करने गया था। टावर से गिरने से उसकी मौत हो गयी। घटना बीते मंगलवार की है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव वाले भी शोक में हैं।



घर का एकलौता कमाऊ व्यक्ति था जगदीश: मृतक जगदीश महतो मलेशिया में एजी पावर कंपनी में काम करता था। वह घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। मृतक अपने पीछे बेटी राधिका कुमारी (7) और आशीष कुमार महतो (5) को छोड़ गया। वहीं इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सरकार से मलेशिया से

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सीएम से की बात

झारखंड के पेयजल आपूर्ति सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को घटना की सूचना मिलते ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है। मलेशिया से युवक के शव गांव में लाया जाये। उन्होंने आप्रीका के केमरून में झारखंड के विभिन्न जिलों के फंसे 41 मजदूरों को वतन वापसी पर भी मुख्यमंत्री को जानकारी देकर वतन वापसी पर पहल करने की बात कही।

शव लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर-परिवार के सदस्यों को काफी विश्वास है कि राज्य सरकार मलेशिया से शव को मंगाने में सहयोग करेगी।

झारखंड कैडर के नौ आइपीएस अफसरों का होगा प्रमोशन

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड कैडर के नौ आइपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। इसको लेकर डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक 19 दिसंबर को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के अलावा कई अधिकारी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड कैडर के 1989 बैच के आइपीएस अफसर व तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह जनवरी 2025 में रिटायर होंगे। वहीं 1992 बैच के आइपीएस अफसर आरके मल्लिक भी जनवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। वे डीजी मुख्यालय हैं। जबकि डीजी डेल एमएल मीणा भी जनवरी 2025 में रिटायर हो जायेंगे। इनके अलावा आइजी के पद पर कार्यरत राजकुमार लक्छा भी जनवरी 2025 में रिटायर होंगे। वे 2005 के आइपीएस अफसर हैं। एक जनवरी 2025 से 2007 बैच के तीन आइपीएस अप्रूप बिस्मर, सुनील भास्कर और मधुर पटेल कर्न्यालाल आइजी रैंक में प्रोन्नत हो जायेंगे। इसके अलावा 2011 बैच के सीनियर एसपी रंक (सीनियर सिलेशन ग्रेड) में प्रोन्नत छह आइपीएस अधिकारी एक जनवरी 2025 से डीआइजी हो जायेंगे। इनमें वंदन झा, वंदन सिन्हा, प्रियदर्शी आलोक, अजीत पीटर डुंगुड़ा, अनुरजन किशोर और अंबर लक्छा शामिल हैं। इसके अलावा 2012 बैच के तीन आइपीएस किशोर कौशल, अंजनी झा और मो. अर्पिता को सिलेशन ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी।

जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करे झारखंड सरकार: हाइकोर्ट

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट में जेपीएससी 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार एवं रिजल्ट जल्द प्रकाशन करने को लेकर दायित्व पवन कुमार वर्मा की रिट याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले 3 माह से रिक्त रहने से कई नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है। झारखंड वेलफेयर स्टेट है यहां विधानसभा चुनाव होने के बाद एक पॉपुलर सरकार भी बन चुकी है, एक बेहतर स्टेट होने के नाते झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरे जाने की उम्मीद की जा रही है।



कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर हाइकोर्ट राज्य सरकार की पॉलिसी मैटर पर हस्तक्षेप नहीं करती है लेकिन यहां मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है। जेपीएससी के लेकिन इस परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी अध्यक्ष के नहीं रहने से पूरी नहीं हो पा रही है। जेपीएससी के कैलेंडर के तहत अगरत माह में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो जानी थी। जेपीएससी के अध्यक्ष के पद रिक्त

होने से कई अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के नुकसान होने एवं उनके करियर पर असर पड़ने की भी संभावना है। झारखंड में नयी सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और सदन की कार्यवाई भी चल रही है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर क्यों अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है? सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित कार्यवाई कर रही है। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष का रिक्त पद जैसे ही भरा जायेगा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाई तत्काल शुरू हो जायेगी।

मीन सरकारी तथा न्यायालयीय कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होगी, कठिन परिश्रम-प्राप्त से व्यापार में लाभ।

Information Brochure

भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ने कंबल और अलाव व्यवस्था की मांग की



आजाद सिपाही संवाददाता

हरिहरगंज/ पलामू। बढ़ते ठंड में कंबल वितरण में देरी को लेकर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सह युवा समाजसेवी राजीव रंजन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार व जिला प्रशासन से जरूरतमंदों के बीच शीघ्र कंबल वितरण तथा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबों व असहायों को बांटे जाने वाले कंबल वितरण में देर होने से बढ़ते ठंड में

जरूरतमंदों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिहरगंज सहित पलामू जिले में पिछले तीन दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस ओर ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। प्रेस वार्ता में पर संजय जायसवाल, शंभू यादव, गोपाल प्रसाद गुप्ता, शंभू सिंह, विजय पासवान, रामचंद्र चौधरी, सत्येंद्र पासवान, राजकुमार चौधरी, केदारनाथ ठाकुर तथा कपिल यादव आदि शामिल थे।

काम में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, होगी कार्रवाई : लोकपाल

आजाद सिपाही संवाददाता

मनातू/ पलामू। मनरेगा लोकपाल शंकर कुमार ने बुधवार को प्रखंड के सभागार भवन में मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रोजगार सेवक को दिशा-निर्देश देते हुए लोकपाल ने कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी रोजगार सेवक की है। उन्होंने रोजगार सेवकों से कहा कि किसी भी कीमत पर मनरेगा कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इस दौरान पंचायत वार सभी योजनाओं की समीक्षा की उसके पश्चात जिस पंचायत में कम मानव दिवस पंचायत के रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता को सख्त निर्देश दिया कि यह सभी पंचायतों में मानव दिवस श्रृजन को बढ़ाएँ। उन्होंने बिरसा सिंचाई कूप,



पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं डोभा, शेड आदि योजनाओं को लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत कर समय कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने बताया कि मनातू प्रखंड में सैकड़ों काम चल रहा कुछ योजना कजरत है और कुछ योजना पूर्ण हो चुका है 21- 22 में जो योजना लंबित है बहुत जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ उन्होंने बताया कि मनातू प्रखंड क्षेत्र के रंगिया पंचायत के गढ़गांव गांव में फर्जी निकासी का मामला सामने आया था हमने उसे गांव पहुंचकर अवलोकन किया तो पाया गया कि मुनिया देवी के

खेत में डोभा निर्माण कार्य उतना ही कराया गया है जितना कि पैसा निकासी किया गया है। लोकपाल ने सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चेतावनी भी दी कि यदि कार्यों में कोई गलती पायी जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मौके पर बीपीओ रणधीर कुमार प्रकाश, कनीय अभियंता नवीन कुमार नीज, विकास कुमार, सहदेव यादव, इकबाल अंसारी, नारद यादव, संजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, रामजी राम समेत सभी रोजगार सेवक उपस्थित थे।

बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का बेहतर प्लेटफॉर्म है विज्ञान प्रदर्शनी : सोमा खंडौत

आजाद सिपाही संवाददाता

विश्रामपुर / पलामू। पूनम तिवारी एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्रामपुर के संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को मॉडल आधारित विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया। जिसका उद्घाटन नप के कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडौत व स्कूल के निदेशक एनके तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। जिसमे बाद अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडौत ने कहा कि यह विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के रचनात्मक प्रतिभा



को निखारने का बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। विज्ञान प्रदर्शनी छात्र-छात्राओं के द्वारा वैज्ञानिक अवधारणाओं, प्रयोगों और परियोजनाओं को प्रस्तुत करने का एक मौका भी उपलब्ध करता है। निदेशक एनके तिवारी ने कहा कि आज हम सभी पूरी तरह विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। इसलिए, छात्र जीवन से ही बच्चों में वैज्ञानिक सोच एवं अभिरुचि को विकसित

करना होगा। यह विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों में प्रतियर्था की भावना को भी जागृत रखेगा। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र-छात्राओं ने हस्तकला,व्यर्थ समाज,विज्ञान से संबंधित विभिन्न मॉडल के द्वारा अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। मौके पर प्राचार्य आर के सिंह, श्याम चंद्रवंशी, चंदन शर्मा, सोनू कुमार, शशि बाला, सानू कुमारी, वर्षा राजक सहित कई लोग मौजूद थे।



आइसीसी रैंकिंग में हैरी ब्रूक नंबर वन पर

एजेंसी

नई दिल्ली। आइसीसी रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक नंबर-1 पर पहुंच गये हैं। उन्होंने अपने ही देश को जो रूट को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को जारी रैंकिंग में ट्रेविस हेड, कामिंडु मोंडिस और टेम्बा बावुमा को भी फायदा हुआ है। बैटर्स की टॉप-10 लिस्ट में इंडियन विकेटकीपर ऋषभ पंत को 3 पायदान का नुकसान हुआ है।

बॉलर्स रैंकिंग में पेसर जसप्रीत बुमराह 890 रैंटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है।



जडेजा छठे स्थान पर है।
हैरी ब्रूक नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज
आइसीसी की ओर से जारी नई टेस्ट रैंकिंग में अब इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर एक बल्लेबाज बन गये हैं।

उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। इससे पहले वे दूसरे स्थान पर थे। अब उनकी रैंटिंग बढ़कर 898 की हो गई है। दूसरे पायदान पर जो रूट है। उनकी रैंटिंग 897 की है। न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन 812



वीडी राम ने लोकसभा में उठाया मंडल डैम के निर्माण का मुद्दा



की जरूरत की परिकल्पना है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने पर 1622.27 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना का कार्य वाफ़्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला।

प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी 2019 को उक्त परियोजना के निर्माण की अधारशिला पलामू में आकर रखी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमण्डल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी। परन्तु डूब क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लगभग 6 महीने कार्य रूका रहा और निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अब तक उक्त कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। कार्य शुरू नहीं होने से जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां उत्पन हो

रही है। विदित है कि डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास तथा शेष कार्यों के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है। परन्तु राज्य सरकार ने उक्त राशि को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों का मुआवजे और पुनर्वास हेतु वितरित नहीं किए जाने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य लंबित है।

सांसद ने कहा कि आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकार को उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाये।

आयुक्त ने जेडआरएस के संतरा बगान और हरिहरगंज के अमरूद बगान का किया अवलोकन

आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र (जेडआरएस), चियाकी परिसर में अवस्थित संतरा बागान का भ्रमण कर संतरा के पेड़ों एवं उसमें लगे फलों का अवलोकन किया। कम बारिश एवं उच्च तापमान वाले पलामू जैसे स्थान पर संतरा के फलों को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। भ्रमण के दौरान उपस्थित जेडआरएस के सह निदेशक डॉ. अखिलेश साह ने आयुक्त को जेडआरएस द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं अनुसंधान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आयुक्त ने संतरा



बागान के साथ-साथ वहां मेढ़ विधि में लगे अरहर की खेती एवं विभिन्न प्रजातियों के गेहूँ की लग रही फसलों का अवलोकन किया। इसके अलावा अनुसंधान केन्द्र में तैयार की जा रही पौधे, पॉली हाउस के माध्यम से खेती की विधि, उनके गुणवत्ता

एवं उपज, आम, आंवला, अमरूद की बागवानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इधर पिछले दिनों आयुक्त ने हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के कटकोबा गांव में बंजर भूमि पर किसान अजय मेहता द्वारा की गई अमरूद की खेती सहित मौसंबी एवं अन्य उद्यानिकी फसलों का अवलोकन कर जानकारी ली। किसान अजय मेहता सैकड़ों एकड़ भूमि पर उद्यानिकी फसलों को लगाया है। आयुक्त को किसान अजय मेहता ने बताया कि उनके बागान में उत्पादित थाई प्रजाति की अमरूद बिहार के पटना, गया एवं अन्य दूसरे शहरों में भेजा जाता है।

अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा

सतबरवा/ पलामू। सतबरवा में बुधवार को भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान सतबरवा मेलाटांड साप्ताहिक हाट बाजार क्षेत्र और एनएच किनारे से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जल पथ प्रमंडल सं0-2 हजारीबाग

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 11 / 2024–2025 (मद—जिला योजना अनाबद्ध निधि)

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost (INR)	Earnest Money (INR)	Cost of BOQ (INR)	Completion period of Work
1	बरकटटा प्रखंड के बेडोकला के सुदन साव के घर से आंगनवाडी केन्द्र तक पी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	2495800	50000	5000	2 Months
2	कटकमसांडी प्रखंड अलर्गंत पंचायत—रोमी ग्राम – छडाव में दीपक ठाकुर के घर से प्रदीप राणा के घर तक पी0 सी0 पी0 पथ का निर्माण कार्य।	2400700	48100	5000	2 Months

- परिमाण विपत्र बिकी का स्थान तिथि एवं समय : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0-2, हजारीबाग। दिनांक 18.12.2024 अपराहन 2:00 बजे तक।
- निविदा प्राप्ति की स्थान तिथि एवं समय : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0-2, हजारीबाग। दिनांक 19.12.2024 पूर्वाहण 11:00 से अपराहन 2:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की स्थान तिथि एवं समय : दिनांक 19.12.2024 को अपराहण 2:30 बजे कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0-2, हजारीबाग।
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं दूरभाष सं0— : कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं0-2, हजारीबाग। 7903709450
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है।

नोट :- निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमंडल सं0-2, हजारीबाग

e- Procurement Cell Office of The Executive Engineer, Building Construction Department, Building Division, Chatra.

अति अल्पकालीन ई—प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई—टेन्डर रेफरेन्स नं०— BCD/EE/CHATRA/ 21/2024-25 दिनांक:— 11.12.2024

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Construction of Bar Association Building at Chatra	Rs. 2,45,58,700.00	11 (Eleven) Months
i	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	18.12.2024	
ii	वेबसाइट पर निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	24-12-2024 को अपराहन 3.00 बजे	
iii	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	26-12-2024 को अपराहन 3.00 बजे	
iv	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	e- Procurement Cell Office of The Executive Engineer, Building Construction Department, Building Division, Chatra	
v	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	9939428677	
vi	ई—प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	9650057169	

- किसी भी प्रकार का बदलाव <http://Sharkhandtenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना <http://Sharkhandtenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

note: UCAN Registration is mandatory for the bidders.

Nodal Officer
e- Procurement Cell
Office of The Executive Engineer,
Building Construction Department,
Building Division, Chatra

PR 341772 (Building) 24-25 (D)



डालसा के लिए अब किन्नर, पूर्व सैनिक व शिक्षक भी करेंगे काम

समाज के हर तबके को जागरूक बनाने के लिए घर-घर पहुंचेगी डालसा की टीम: न्यायाधीश

आजाद सिपाही संवाददाता
धनबाद। समाज के हर तबके तक कानूनी जागरूकता फैलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाने में मदद करने के लिए किन्नर, पूर्व सैनिक, पूर्व शिक्षक भी डालसा के लिए काम करेंगे। झालसा के निर्देश पर समाज के हर तबके से जुड़े ऐसे 10 लोगों को पीएलवी नियुक्त किया गया है। झालसा के निर्देश पर 10 नए पारा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति के बाद बुधवार से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी व अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने



प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र तिवारी व अन्य गणगण्य लोग।

किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आम लोगों को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कई सार्थक प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न इलाकों में पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की

गई है। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) सचिव राकेश रोशन ने बताया कि इस बार समाज के हर तबके से डालसा के प्रतिनिधि के रूप में पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की गई है, जिसमें किन्नर समाज से श्वेता किन्नर, शिवानी किन्नर,

रिटायर्ड सैनिक अशोक कुमार सिंह, डॉ रुद्र नारायण दे, डॉ प्राण मोहन, शिक्षक वर्ग से उदय राम, संतोष कुमार, अजरुदीन अंसारी, राजेश कुमार सिन्हा और सुबुल केशर शामिल हैं जो प्रशिक्षण के बाद डालसा के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। नवनियुक्त पीएलवी

श्वेता किन्नर व शिवानी किन्नर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज डालसा के साथ जुड़कर वह गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। न्यायपालिका ने उन्हें इस काबिल समझा और उन्हें सम्मान दिया। कहा कि गरीब और असहाय लोग भी न्याय पा सकें और लोगों के छोटे-छोटे झगड़े शुरुआती दौर पर ही आपसी बातचीत, समझौते के साथ सुलझ सकें। इसके लिए हम सभी पैरा लीगल वॉलंटियर गांव-समाज में जाकर न्याय के लिए प्रयासरत लोगों को त्वरित न्याय दिलवाने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में प्रशासन के सहयोग से काम करेंगे।



योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस कारण ये लोग सभी सुविधाओं से वंचित रह गये। हालांकि यहां रहने वाली एक लाख की आबादी विधायक और सांसद चुनती है, लेकिन ये लोग गांव की सरकार नहीं चुन पाते हैं। नियोजन, विद्युत, सड़क, पेयजल, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी इन क्षेत्रों में जरूर है। शहर से समीप होने के बावजूद यह क्षेत्र सभी मूलभूत सुविधाओं

से वंचित है। इस लिए आग्रह है कि सभी मामले को बिंदुवार व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लेते हुए निदान करें। इस अवसर पर राज कुमार सिंह, प्रदीप मंडल, मिथुन मंडल, महेश मंडल, जन्मजय महतो, अमित कुमार, गफफार अंसारी, राजन सिंह, अजीत कुमार, संतोष मुर्मू, सरोज कुमार, विनोद राय और कलाम अंसारी उपस्थित थे।

घनी आबादी में नाले में गिरा तेल टैंकर, बड़ा हादसा टला



नाले में फंसे तेल टैंकर को निकालने का प्रयास करता चालक।

आजाद सिपाही संवाददाता
झरिया। बस्ताकोला राजपुर में संचालित देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए 40 हजार लीटर तेल लेकर जा रहा एक टैंकर बस्ताकोला के घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क किनारे एक नाले में गिर गया। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा कि बनारस से 40 हजार लीटर तेल लेकर चला हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में जा रहा था। लेकिन तंगी गली होने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो दिया और टैंकर के बाए साइड का चक्का सड़क किनारे नाली में जा गिरा। वहां सड़क के दोनों किनारे कई घर हैं, और यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उधर, घटना की सूचना

पाते ही मौके पर पहुंचे देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी में बड़े वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बने हुए हैं। पर शॉर्टकट के चक्कर में कुछ चालक घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इस रास्ते पर आने के लिए उन्होंने टैंकर के चालक को फटकार भी लगाई। इधर, टैंकर चालक ने बताया कि उन्हें इस रास्ते पर जाने के लिए देवप्रभा कंपनी के मामा नामक व्यक्ति ने कहा था। वह इस तंग गली से अनजान था। फिलहाल इस दुर्घटना के बाद से इस मार्ग पर आवागमन बाधित है। कंपनी क्रेन की मदद से टैंकर को नाली से बाहर निकाल कर आगे ले गया।

रक्तदान शिविर का आयोजन

धनबाद (आजाद सिपाही)। भारतीय एकता शेर सेना सामाजिक संस्था के स्थापना दिवस पर बुधवार को रणधीर प्रसाद वर्मा चौक के निकट धरना स्थल पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। जिसमें भारतीय एकता शेर सेना के संस्थापक रंजन गुप्ता, मृत्युंजय चौरसिया, अमित कुमार, उदय शंकर प्रसाद, ऋषिकेश प्रसाद, रवींद्र कुमार सिंह की सक्रिय भूमिका रही। इस दौरान 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेजिस्ट्रेट नारायण राम एवं रविन्द्र नाथ ठाकुर के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में सिंदरी की भाजपा नेत्री तारा देवी भी शामिल हुईं।

चिंता : रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन भारत की एकता-अखंडता के लिए भाषायी भेदभाव घातक : जलेश्वर महतो

आजाद सिपाही संवाददाता
महुदा। रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बुधवार को भाषाओं के माध्यम से एकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय प्रशासक मधुसुधन महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों व कॉलेज प्राचार्य ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीएड सत्र-2024-26 के अंशु तिवारी, दीपिका पूजा, विजेता, उज्ज्वल, याशी, नवीन, प्रियेश, सौरभ, चंदना,



पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो का स्वागत करते रवि महतो स्मारक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजेश कुमार यादव व अन्य

रवि, नितिश आदि विद्यार्थियों ने अपने-अपने विचार पेश किये। इस बीच जलेश्वर महतो ने अपने संबोधन में कहा कि आज बदलते परिवेश में भाषायी भेदभाव बढ़ा है जो देश की एकता एवं अखंडता

के लिए घातक है। वहीं विद्यालय प्रशासक मधुसुधन महतो ने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भाषा में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में भी भाषाओं की नैतिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वहीं, प्राचार्य डॉ राजेश कुमार यादव ने कहा कि आज देश के विघटनकारी तत्वों में भाषा का भी प्रमुख स्थान है। भाषा विचारों एवं भावों का प्रकटीकरण है। भारत में भाषायी विविधता है। इसमें किसी

प्रकार का भेदभाव से बचने की आवश्यकता है। कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ सजल बनर्जी ने कहा कि ज्यदा से ज्यदा भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अपनी भाषा में सरलता, सहजता एवं मधुरता लाना शिक्षक का प्रमुख जिम्मेदारी है। वहीं, डीएलएड के विभागाध्यक्ष डॉ नवीन मंडल ने कहा कि इस संसार में सभी प्राणी एवं जवी-जंतुओं की अपनी भाषा होती है। उसको समझने की आवश्यकता है। इस मौके पर विजय महतो, डॉ मंजू कुमारी, रविकांत पांडेय, सबिता कुमारी, त्रिलोकीनाथ बिंद, मोहन लाल महतो के अलावा संचालन शिवानंद एवं अजीत आदि उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका से मिलकर विस्थापितों ने समस्याओं से अवगत कराया

आजाद सिपाही संवाददाता

बोकारो। विधायक श्वेता सिंह ने बुधवार को बोकारो के उत्तरी विस्थापित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रांची जाकर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक श्वेता सिंह ने मंत्री को अवगत करवाया कि विगत 75 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बोकारो के विस्थापितों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बताते चले कि बीएसएल प्लांट के निर्माण के बाद उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों को ना तो पंचायत में शामिल किया गया और ना ही किसी अन्य व्यवस्था में, जिसके कारण इन गांवों में रहने वाले गरीब आदिवासियों और अन्य जातियों को सरकार के किसी भी



किस्त जारी करें। सभी कार्य का अविलंब शत प्रतिशत जियो देग करें। इसके बाद लाभुकों के घर जाकर कार्य में आ रही समस्या को तुरंत दूर करें। उन्होंने चेतावनी देकर कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में

बीडीओ महादेव कुमार महतो, बीपीओ मनोहर दास, आशीष कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आरके मिश्रा, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डब्ल्यू सुरेश कुमार, पंचायत सेवक रितु कुमारी, सोनम कुमारी और ओम प्रकाश आदि उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग				
झारखण्ड सरकार विद्युत कार्यपालक अभियन्ता				
विद्युत कार्य प्रमण्डल, इंजीनियरिंग हॉस्टल नं०-2 धुर्वा, राँची				
अल्पकालीन ई-प्रोक्वोरमेंट सूचना				
ई-निविदा प्रसंग सं०- Energy/EWD/Ranchi/89/2024-25				
दिनांक- 10/12/2024				
1.	कार्य का नाम	प्रारंभित राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रपन की राशि
1.	प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची एम०डी०आई० भवन, माननीय मुख्य मंत्री के समामार, ट्रेजरी भवन, कैपिटल भवन, बैरक प्रोजेक्ट भवन में अधिष्ठापित विद्युतीय उपकरण, फैल, कैब्स लाईट एवं 6 अदर 200 कै०वी०/१०, 1 अदर 250 कै०वी०/१० एवं 1 अदर 500 कै०वी०/१० जलित के वार्षिक सम्पूर्ण का कार्य 11 अदर लिट लिट के संचालन का कार्य।	1,47,94,939-00	10,000-00	2,96,000-00
2.	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	23.12.2024		
3.	निविदा जमा करने की तिथि	24.12.2024 के 10.30 बजे पूर्वान से 02.01.2025 के 2.00 बजे अपराह्न तक		
4.	निविदा खोलने की तिथि	03.01.2025 को 3.00 बजे अपराह्न में		
5.	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विस्तृत कार्य प्रमण्डल, राँची।		
6.	निविदा खोलने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	मुख्य विद्युत अभियन्ता, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची।		
7.	ई प्रोक्वोरमेंट प्रोजेक्ट का फोन नं०/ई० मेल	0651-2490069/electricalexecutiveengineerewd@gmail.com		
Note :- Tender Fee and Earnest Money Deposit (EMD) are to be paid through online mode only as per instruction of IT Dept. Govt. of Jharkhand Letter no.-120 Dated- 03-10-2023.				
निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट http://jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।				
विद्युत कार्यपालक अभियन्ता विद्युत कार्य प्रमण्डल,राँची				
PR 341752 (Energy)24-25*D				

कार्यालय :- जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा सदर अस्पताल परिसर, गढ़वा।

राज्य योजना अंतर्गत गढ़वा जिला के आदिम जनजाति समुदाय (PVTG) बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्रथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चलन्तम ग्राम क्लीनिक के संचालन हेतु आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक का चयन हेतु रिक्तियों के आलोक में Walk in Interview हेतु पुनर्विज्ञान।

विज्ञापन संख्या :-07/2024

साक्षात्कार की तिथि :-17.12.2024

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, गढ़वा के पत्रांक- 05/पी-16/2023-33 (6)व् योजना, स्वा०, गढ़वा दिनांक- 25.05.2023 के द्वारा राज्य के आदिम जनजाति समुदाय (PVTG) बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्रथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निमित्त " चलंत ग्राम क्लीनिक" के संचालन हेतु आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहाय की Walk in Interview के आधार पर पूर्व में दो बार आयुष चिकित्सको तथा चिकित्सा सहायकों चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था किन्तु आरक्षण कोटि के अनुसार अय्यावेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निम्नांकित पद रिक्त रह गये हैं।
"चलंत ग्राम क्लीनिक" गढ़वा जिला के लिए रिक्तियों के आलोक में आयुष चिकित्सक तथा चिकित्सा सहायक की सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक अर्हता, मानदेय एवं अन्य विवरण निम्नांकित है:-

क्र० सं०	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कोटिवार पदों की सं०	मानदेय	कार्य का समय
			कोटि	रिक्त पदों की सं०	
1	आयुष चिकित्सक	Bachelor in Ayurved/Homoeopathy/unani with working Knowledge of Computer	SC 05 ST 02 TOTAL 07	रु 21000/- (कुल 26 कार्य दिवस)	09:00 AM To 06:00 PM

- चयनित आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक द्वारा भविष्य में नियमितिकरण हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- Walk In Interview में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- "चलंत ग्राम क्लीनिक" के संचालन हेतु आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक के द्वारा मिलकर स्वयं व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए 5000 (पांच हजार) रूपया प्रतिमाह देय होगा।

नोट :- "चलंत ग्राम" क्लीनिक के लिए चयन आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक द्वारा किया जाने वाला कार्य :-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत "चलंत ग्राम क्लीनिक" में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कियान्वयन सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समयवधि में ओपी०डी० का संचालन
- प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल
- ऐमिबिया और अन्य गैर संवारी रोग अंतर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह की जांच।
- टी०बी० एवं मलेरिया का पता लगाने के लिए बलगम एवं रक्त-पट्ट संग्रह।
- अन्य सरकारी / गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
- विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्यक्रमों / योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना
- समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य का निष्पादन

उक्त आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक के चयन करने हेतु अन्य शर्तें, अर्हता, आवेदन-पत्र इत्यादि का विवरण गढ़वा जिला के वेबसाइट www.garhwa.nic.in अथवा जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के कार्यालय के सूचना-पट्ट से उपलब्ध की जा सकती है।

इच्छुक अर्थी, आयुष चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायक के पद पर चयन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय गढ़वा में दिनांक 17.12.2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य बाधित मूल प्रमाण-पत्रों एवं छायाप्रति (01) के साथ Walk in Interview हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

80/-
अभौतिक शाल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा।

PR 341741 (Health Med Edu and Family Welfare) 24-25 (D)

